मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का हुआ शुभारंभ : किसानों को सलाना प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रूपए तक की होगी आय

- निजी भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को मिलेगा बढ़ावा-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की योजना की वर्चुअल शुरुआत, रायगढ़ में अड़बहाल में हुआ शुभारंभ
- वनोपज के परिवहन के लिए नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम लांच

रायगढ़। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष से योजना का ऑनलाइन शुभारंभ कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण-संवर्धन तथा हरियाली के प्रसार के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। इस योजना से किसानों के निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को वृक्षारोपण के लिए अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर वन संसाधन अधिकारों को लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए मोबाईल आधारित एफआरए टूल का लोकार्पण किया और वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने तथा व्यापारियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद महेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1458 हितग्राहियों के खाते में कुल 22 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 'मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना' वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों के लिए आर्थिक दृष्टि से, पर्यावरण, सॉइल हेल्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जंगल और यहां की जैव विविधता छत्तीसगढ़ की पहचान है। हमारी कला, संस्कृति, परम्पराएं, दर्शन, चिंतन, आध्यात्म, इतिहास सब कुछ हमारे जंगलों से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के वन पूरे देश की धरोहर है। इन वनों से पूरे देश का पर्यावरण जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे जंगल बचे रहे, हमारा पर्यावरण बचा रहे, जंगल से जुड़ी हमारी गौरवशाली संस्कृति बची रहे और खूब फले-फूले इस दिशा में बीते चार वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यह योजना देश में एक अनूठी योजना है, जिसमें वाणिज्यिक प्रजातियों का वृक्षारोपण कर निजी व्यक्ति, संस्था अथवा कम्पनियों के माध्यम से अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं। यह केवल वृक्षारोपण की योजना न होकर देश के जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी हमारी सहभागिता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्चुअल आयोजित कार्यक्रम में रायगढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम रायगढ़ विकासखंड के अड़बहाल में किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, जिला पंचायत सदस्य संगीता गुप्ता, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टाइलो मंडावी, सभापति कृषि स्थाई समिति जनपद पंचायत रायगढ़ रामकुमार भगत, रामलाल पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

वृक्ष संपदा योजना पर एक नजर

डीएफओ रायगढ़ स्टाइलो मंडावी ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर (अधिकतम 5000 पौधे) पौधों का रोपण हेतु 100 प्रतिशत तथा 05 एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। सहयोगी संस्था अथवा निजी कम्पनियों की सहभागिता से कृषकों को उनके उत्पाद के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध होगी तथा शासन पर वित्तीय भार भी कम होगा। टिशू कल्चर सागौन, टिशू कल्चर बांस एवं मिलिया डूबिया वृक्षों के परिपक्व होने के पश्चात् निर्धारित समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा क्रय किया जाएगा। इस योजना में सहयोगी संस्था अथवा निजी कम्पनियों की भी सहभागिता होगी। उनके द्वारा वित्तीय सहभागिता के साथ शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर हितग्राहियों के वृक्षों की वापस खरीदी भी की जाएगी।

रायगढ़ में वृक्षारोपण के लिए 2564 एकड़ भूमि चिन्हांकित

विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ के दोनों वनमंडलों में 2564 एकड़ को वृक्षारोपण के लिए चिन्हांकित किया गया है। जिसमें वन विभाग के तहत 1139, कृषि विभाग के अंतर्गत 957, उद्यानिकी के 270, रेशम विभाग के तहत 198 एकड़ में किसानों द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा।

बीमा योजना के 84 लाख रुपए वितरित- कार्यक्रम में शहीद महेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिला यूनियन अंतर्गत 23 हितग्राहियों को उनके तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर चौरासी लाख पचपन हजार रुपए की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ऑनलाइन जारी की गयी। इनमें से कुछ हितग्राही जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित थे। जिन्हे जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल द्वारा चेक प्रदान किया गया।

नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम लॉन्च-मुख्यमंत्री बघेल ने वन विभाग द्वारा वनोपज के परिवहन हेतु तैयार कराए गए नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम को लॉन्च किया। इस सुविधा के अंतर्गत आवेदक ट्रांजिट परमिट के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा वन विभाग ऑनलाईन ट्रांजिट परमिट जारी करेगा। अंतरराज्यीय सीमा में नये टी.पी.की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ एनटीपीएस योजना को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है।

मोबाईल एप का हुआ लोकार्पण- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जारी करने की प्रक्रिया को ट्रेक करने हेतु मोबाइल एप का लोकार्पण भी किया। इस मोबाइल एप के उपयोग से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के आवेदन से लेकर अधिकार प्राप्ति तक 12 स्तर की प्रक्रिया है तथा 18 प्रपत्रों में जानकारी भरी जाती है। मोबाइल एप के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का मॉनिटरिंग भी की जा सकती है।

महत्वपूर्ण एवं खास

54 वाहनों पर छाल पुलिस ने की चालानी कार्यवाही

रायगढ़। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के सभी थाना, चौकी क्षेत्र अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज शाम थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया के नेतृत्व में छाल स्टाफ द्वारा भारी वाहनों के साथ मध्यम एवं दुपहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किया गया एवं वाहन चालकों को रफ्तार पर नियंत्रण रखने और रात्रि में अपर-डिपर लाइट का प्रयोग कर सड़क के बाई ओर चलने की हिदायत दिया गया है। साथ ही बेवजह सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन खड़ी करने वालों पर छाल पुलिस धारा 283 आईपीसी की कार्यवाही की जा रही है। इस माह 06 वाहनों पर धारा 283 आईपीसी के तहत कार्यवाही कर वाहन चालकों को कोर्ट पेश किया गया है। आज शाम तक छाल पुलिस ने 54 वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही कर 16,800 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया है जिसे राजस्व खाते में जमा किया जावेगा।

तारमिस्त्री परीक्षा के लिए 01 अप्रैल से आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत संभागीय अनुज्ञापन समिति (विद्युत)रायगढ़ के द्वारा तारमिस्त्री परीक्षा आगामी माह जुलाई में आयोजित की जाएगी। जिसके लिए 1 से 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। जिला-रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ के आवेदन कर्ता परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र कार्यालय अवधि में कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि.सु.)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक छ.ग.शासन रायगढ़ संभाग रायगढ़ दुर्गा चौक उत्तर चक्रधरनगर रायगढ़ से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में संपर्क कर सकते है।

त्यौहारों के मद्देनजर रायगढ़ पुलिस ने शहर में बढ़ाई चौकसी

- एडिशनल एसपी और सीएसपी ने की मार्केट एरिया में पैदल पेट्रोलिंग
- अव्यवस्थित दुकानदारों को व्यवस्था बनाने की दी हिदायत

रायगढ़। आज से नवरात प्रारंभ होने जा रहा है , इस दौरान शहर में कई सामाजिक संगठनों के विविध कार्यक्रम प्रस्तावित हैं , जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा पुलिस अधिकारियों को विजुअल पेट्रोलिंग के साथ शहर में पाइंट ड्यूटी बढाकर शाम के समय सभी एरिया में पैदल गश्त कराने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों के पालन में व्यवस्था की जांच पर आज शाम एडिशनल एसपी संजय महादेवा एवं सीएसपी अभिनव उपाध्याय स्वयं शहर के प्रमुख चौंक-चौराहों में कोतवाली पुलिस के साथ फुट पेट्रोलिंग किया गया। पुलिस अधिकारियों के साथ एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा भी मौजूद थे। पेट्रोलिंग दौरान सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल रखे एवं अव्यवस्थित दुकानों, बेतरतीब पार्किंग को देखकर अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठान संचालक को सड़क पर से सामान हटाने तथा यातायात व्यवस्थित करने के निर्देश दिया गया है। वहीं यातायात पुलिस भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर सड़क पर खड़ी वाहनों पर लगातार चालानी कार्यवाही की जा रही है।

केलो नहर से 34 किमी दूर कठली में पहुंच रहा पानी

- नेतनागर की बांध से दूरी करीब 25 किमी
- नेतनागर और रेंगालपाली टेल एरिया इसलिए क्योंकि आगे प्रदेश की सीमा होती है खत्म, पानी के बहाव से नही है संबंध

रायगढ़। केलो परियोजना के तहत नहरों के निर्माण होने से गांवों तक पानी पहुंच रहा है। जिसका उपयोग गांव में किसान खेती-किसानी के साथ ही पेयजल और निस्तारी के लिए कर रहे हैं। केलो बांध से लगभग 34 किमी दूर पुसौर विकासखंड का कठली गांव है। यहां पर केलो नहर का काम पूरा हो चुका है और यहां नहर से पानी भी पहुंच रहा है।

कार्यपालन अभियंता पी.आर. फूलेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि केलो परियोजना के तहत बन रहे नहरों में कई जगहों पर सभी पैच के कार्य पूर्ण होने पर नहरों का पानी वहां पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि केलो बांध से तकरीबन 34 कि.मी. दूर स्थिति पुसौर विकासखंड के कठली गांव में पानी पहुंच रहा है। उन्होंने नेतनागर के बारे में बताया कि इसकी दूरी बांध से करीब 25 किमी है। इसके साथ ही यह बांध से लगभग 27 मीटर डाउन में है। बांध की ऊंचाई लगभग 24.22 मीटर है। ऐसे में नेतनागर तक पानी नहीं पहुंचने वाली बात सही नही है। उन्होंने कहा कि कठली नेतनागर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने आगे बताया कि नेतनागर और रेंगालपाली के बाद प्रदेश की सीमा खत्म हो जाती है। इसलिए यह नहर का अंतिम छोर है। इसका बहाव से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो बांध की ऊंचाई के अनुपात में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। जिससे पानी का वेग बढ़ जाता है। यही कारण है कि 34 किमी दूर कठली तक पानी पहुंच रहा है। ऐसे में नेतनागर तक पानी नही पहुंचने वाली बात सही नहीं है।

गौरतलब है कि सिंचाई विभाग केलो नहरों का काम तेजी से पूरा करवाने में लगा हुआ है। परियोजना के पूरे होने से रायगढ़ और सक्ती जिले के 175 गांवो के 22810 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा सतही जल से मिलेगी। नहर के पानी का उपयोग जलस्रोतों को भरने, पेयजल, निस्तार और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी होगा।

मछली पालन विभाग को हेचरी व उद्यानिकी विभाग को पॉली हाउस निर्माण हेतु कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश : कैंप लगाकर छूटे किसानों का बनाएं केसीसी

- जिले के प्रगतिशील किसानों को नवाचार के लिए करें प्रोत्साहित-कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा
- जल संवर्धन एवं भू-जल स्तर में वृद्धि हेतु ब्लॉक स्तर पर बनाएं कार्ययोजना
- मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत भूमि चिन्हांकन के दिए निर्देश

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वन, कृषि, भूमि संरक्षण, पशु चिकित्सा, सहकारिता, मछली पालन, उद्यानिकी, अपेक्स बैंक सहित बीज निगम विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सिन्हा ने विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के किसान प्रगतिशील है, उन्हें कृषि के क्षेत्र में नवाचार हेतु प्रोत्साहित करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि जिले के किसान नवाचार में आगे आए एवं उन्हें उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने कृषि, मछली, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार हेतु ब्लॉक स्तर पर विभागीय कार्ययोजना बनाई जाए। जिससे जिले के किसान उन कार्यों को देख कर प्रोत्साहित हों सके। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में नवीन तकनीक के समावेश के फलस्वरूप बेहतर लाभ अर्जित किया जा सकता है। जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। जिसके लिए उन्होंने मछली पालन विभाग को जिले में मछली पालन हेतु हेचरी निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने एवं उद्यानिकी विभाग को पॉली हाऊस बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशु पालन विभाग को मुर्गी के स्थानीय मांग के अनुरूप हेचरी निर्माण तथा ग्रामीणों की आय वृद्धि के लिए पशु प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने मिलेट मिशन की समीक्षा की। वन विभाग द्वारा बताया गया कि मिलेट मिशन अंतर्गत रागी, कोदो, कुटकी की खरीदी की गई है, इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि रागी, कोदो और ज्वार के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। जिस पर कलेक्टर सिन्हा ने बीज की उपलब्धता की जानकारी ली, उन्होंने संबंधित अधिकारी को आवश्यकतानुसार मांग भेजने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने केसीसी प्रगति समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को छूटे किसानों की केसीसी बनाने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पत्र प्राप्त किसानों को फोकस कर उनका केसीसी बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास खंडों में आगामी दिनों में होने वाले किसान मेला की जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को बेहतर समन्वय के माध्यम से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए गोबर ब्रिकी में बढ़ोतरी करने एवं वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने भुगतान की जानकारी ली, अपेक्स बैंक के अधिकारी द्वारा बताया गया अकाउंट नंबर गलत होने से कुछ भुगतान लंबित है। कलेक्टर सिन्हा ने संबंधित अधिकारी को लंबित भुगतान के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

बैठक में डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मण्डावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, अपेक्स बैंक, बीज निगम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जल संवर्धन की दिशा में करें कार्य, ब्लाक स्तर पर बनाये कार्ययोजना- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कृषि विभाग को जल संवर्धन की दिशा में विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। जिससे जिले के विभिन्न क्षेत्र में सिंचित भूमि का विस्तार हो सके।

संत बाबा गुरू घासीदास स्मृति शासकीय चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट का हुआ शुभारंभ

रायगढ़। संत बाबा गुरूघासी जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में डायलिसिस यूनिट का आज शुभारंभ हुआ। वर्तमान में 2 यूनिट डायलिसिस मशीन का संचालन शुरू हुआ है। डायलिसिस यूनिट शुरू होने से रायगढ़ अंचल के किडनी मरीजों को लाभ मिलेगा। शुभारंभ अवसर पर स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के डीन डॉ.पी.एम.लूका, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ.एम. के.मिंज एवं मेडिसीन विभागाध्यक्ष डॉ.संविता अहेरवाल, सह प्राध्यापक डॉ.जितेन्द्र कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक डॉ.नरेश पटेल, सीनियर रेसीडेंट डॉ.सीमा पटेल तथा डायलिसिस यूनिट के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।

100 स्कूली बच्चों ने किया जिले के विभिन्न स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण

रायगढ़। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अंतर्गत रायगढ़ जिले में समग्र शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी बी.बाखला के निर्देशन में जिले के एलिमेंट्री स्कूल के कक्षा 6 से 8 पढने वाले छात्र-छात्राओं का एकदिवसीय एक्स्पोजर विजिट शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। विदित हो कि समग्र शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए इस एक्स्पोजर विजिट हेतु जिले के विभिन्न विकास खंडों से लगभग 100 बच्चे सम्मिलित हुए एक्स्पोजर विजिट अंतर्गत स्कूली छात्र-छात्राओं ने रायगढ़ के प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण किया।

सर्वप्रथम सभी बच्चों ने रायगढ़ के स्थानीय पुरातात्विक संग्रहालय का अवलोकन किया तथा रायगढ़ राजघराने की विरासत एवं रायगढ़ के आसपास के प्रागैतिहासिक काल के तहत विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुओं का अवलोकन किया। इसी कड़ी में स्कूली छात्र-छात्राओं ने रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध एकताल झारा शिल्प के शिल्प कला व शिल्प सामग्रियों का भी अवलोकन किया।

उक्त एक्स्पोजर विजिट के दौरान बच्चों ने स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई कॉलेज रायगढ़ का भी भ्रमण किया जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के मशीनों कलपुर्जो उनकी उपयोगिता तथा उनके संचालन की बारीकियों से अवगत कराया गया।

इसी क्रम में स्कूली बच्चों ने इंदिरा बिहार रायगढ़, कृषि कॉलेज रायगढ़, जिला कलेक्ट्रेट एवं कोसमनारा में सत्यनारायण बाबा धाम का भी शैक्षणिक भ्रमण किया। उक्त शैक्षणिक भ्रमण में सहयोगी शिक्षक के रूप में सौरभ पटेल, सीपी डनसेना, रजनी पटेल, आशा किरण साहू, निशा गौतम, उर्वशी साहू, गोमती पटेल, रविंद्र पटेल, दीपक रात्रे, दीपक पटेल, विकास पटेल व रामचंद्र उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना : 129 करोड़ से संवरेंगे रायगढ़ के स्कूल

- 99 करोड़ की राशि स्वीकृत, पहले 30 करोड़ रुपए किए जा चुके हैं मंजूर
- योजना में शामिल सर्वाधिक स्कूल रायगढ़ के, प्रदेश के बजट का 26 प्रतिशत मिला जिले को
- 97 करोड़ से 1536 स्कूलों की होगी मरम्मत
- 25 स्कूलों के लिए डीएमएफ से 1.95 करोड़ स्वीकृत
- समग्र शिक्षा के 62 स्कूलों के काम मंजूर, इनके लिए पृथक से होगी राशि जारी
- स्कूलों में मरम्मत के साथ अतिरिक्त कक्षों का भी होगा निर्माण

रायगढ़। अगले सत्र से पहले स्कूलों की मरम्मत को शासन ने प्राथमिकता में रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं इस संबंध में 'मुख्यमंत्री स्कूल जतन' योजना की घोषणा की है। शासन द्वारा स्कूलों का सर्वे कर मरम्मत योग्य स्कूलों की जानकारी मंगाई थी। जिसके आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय से बजट जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि जारी बजट में रायगढ़ के स्कूलों के मरम्मत के लिए 97 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। शासन द्वारा पूरे प्रदेश के स्कूलों के लिए 369 करोड़ 83 लाख रुपए जारी किए हैं। जिसमें से एक चौथाई से अधिक राशि रायगढ़ जिले को प्राप्त हुआ है।

इसके पूर्व शासन ने स्कूलों के मरम्मत के लिए 10 करोड़ 11 लाख रुपए और 1962 से पहले निर्मित पहले के स्कूलों के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इसके साथ ही जिले में सीएसआर से 15 करोड़ 72 लाख और डीएमएफ से 2 करोड़ 01 लाख रुपए की स्वीकृति कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने दी है। इन सभी को मिलाकर जिले के स्कूलों के लिए 128 करोड़ 66 लाख रुपए स्कूलों की मरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने अपनी पदस्थापना के साथ ही जिले में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए विभागीय काम-काज की गहन समीक्षा की। जिसमें स्कूलों में मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष निर्माण की जरूरत प्रमुखता से सामने आयी। जनचौपाल में भी इस बाबत कई आवेदन भी प्राप्त होते रहते थे। इसको देखते हुए कलेक्टर सिन्हा ने जिला शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूलों का सर्वे करवाकर प्रपोजल तैयार करने के लिए निर्देशित किया था। जिसके पश्चात जिले के सभी विकासखंडों में ऐसे स्कूल जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है उसकी लिस्ट तैयार कर शासन को भेजा गया। कलेक्टर सिन्हा ने स्वयं इस कार्य की नियमित समीक्षा की। जिसका परिणाम ये रहा कि रायगढ़ जिले के सर्वाधिक स्कूलों के मरम्मत कार्य प्रस्ताव में शामिल किए गए तथा जारी बजट का लगभग एक तिहाई रायगढ़ जिले को मिला।

जिले में इतने स्कूलों का होगा कायाकल्प- शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के मुताबिक डीपीआई मद से 1536 स्कूलों के लिए 97 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डीएमएफ से 25 स्कूलों के लिए कुल 1 करोड़ 95 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके पूर्व के आदेश मुताबिक 10 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है। इस राशि से जिले के 182 स्कूलों में मरम्मत कार्य होंगे तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया जाएगा। इसी के साथ ही 1962 के पूर्व निर्मित स्कूल भवनों के मरम्मत व रखरखाव के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अगले शिक्षा सत्र से 31 आत्मानंद स्कूल और प्रारंभ हो रहे हैं इसके उन्नयन के लिए कलेक्टर सिन्हा ने सीएसआर मद से 15 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ समग्र शिक्षा अभियान के तहत 62 स्कूलों में कार्यों को मंजूरी दी गयी है। जिसकी राशि पृथक से राज्य शासन द्वारा जारी की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480